

HINDI FILE



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY PRACTICE QUESTIONS

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : SEPTEMBER 3, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

दैनिक अभ्यास प्रश्न - स्थैतिक भाग से

1. भारत में उत्तर-औपनिवेशिक काल (Late Colonial Period) के दौरान राजनीतिक घटनाक्रमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1940 के अगस्त प्रस्ताव (August Offer) ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था।
- क्रिप्स प्रस्तावों (Cripps Proposals) ने प्रांतों को युद्ध के बाद प्रस्तावित भारतीय संघ से अलग होने (बाहर रहने) की अनुमति दी थी।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- कोई नहीं
- दोनों
- निर्धारित नहीं किया जा सकता

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- कथन 1 गलत है।** अगस्त प्रस्ताव (1940) ने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं किया था। इसने केवल वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का प्रस्ताव रखा और भविष्य में भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने के अधिकार को मान्यता दी थी, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से निर्वाचित एक संप्रभु संविधान सभा को।
- कथन 2 सही है।** क्रिप्स मिशन (1942) ने प्रस्ताव दिया था कि युद्ध के बाद एक भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा और जो प्रांत इसमें शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं, वे अपनी अलग संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकते हैं। इस प्रावधान की तीखी आलोचना की गई थी क्योंकि इसने अप्रत्यक्ष रूप से विभाजन की संभावना को स्वीकार कर लिया था और एक अनिवार्य संघीय संघ के विचार को कमजोर कर दिया था।

अतः, केवल एक कथन सही है।

2. निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प यह सबसे अच्छी व्याख्या करता है कि स्थानिक प्रजातियाँ (Endemic Species) आमतौर पर व्यापक रूप से वितरित प्रजातियों की तुलना में विलुप्ति के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों मानी जाती हैं?

- (a) वे अनिवार्य रूप से पारिस्थितिकी प्रणालियों में उच्च पोषण स्तरों (Higher Trophic Levels) पर होती हैं
- (b) वे जलवायु परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन करने में असमर्थ होती हैं
- (c) उनका सीमित भौगोलिक वितरण उन्हें पर्यावास व्यवधान (Habitat Disturbance) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है
- (d) उनके पास प्रवासी प्रजातियों की तुलना में हमेशा कम प्रजनन क्षमता होती है

उत्तर: (c)

व्याख्या:

स्थानिक प्रजातियाँ (Endemic Species) वे होती हैं जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं और प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं पाई जाती हैं। उनका सीमित दायरा उन्हें पर्यावास के विनाश, पर्यावरणीय व्यवधानों, आक्रामक प्रजातियों और जलवायु से जुड़े बदलावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है।

- विकल्प (a) गलत है क्योंकि स्थानिकता का पोषण स्तर (ट्रॉफिक लेवल) से कोई आवश्यक संबंध नहीं है।
- विकल्प (b) बहुत अधिक पूर्ण (अतिशयोक्तिपूर्ण) है; स्थानिक प्रजातियाँ कुछ परिवर्तनों के अनुकूल हो सकती हैं, लेकिन सीमित वितरण ही उनका मुख्य जोखिम बना रहता है।
- विकल्प (d) गलत है क्योंकि संवेदनशीलता हमेशा प्रजनन क्षमता से जुड़ी नहीं होती है।

इस प्रकार, सीमित भौगोलिक प्रसार और पर्यावास विशेषज्ञता (Habitat Specialization) स्थानिक प्रजातियों को विशेष रूप से विलुप्ति के प्रति संवेदनशील बनाती है।

3. भारत में आर्थिक सुधारों और बाहरी क्षेत्र प्रबंधन (External Sector Management) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मुद्रा का अवमूल्यन (Currency Devaluation) आयात मांग की स्थितियों की परवाह किए बिना अनिवार्य रूप से व्यापार संतुलन में सुधार की ओर ले जाता है।
2. आयात का उदारीकरण (Liberalization of Imports) शुरू में चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) को बढ़ा सकता है, भले ही यह दीर्घकालिक औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता का समर्थन करता हो।
3. केवल विनिमय दर समायोजन (Exchange Rate Adjustment) ही स्थायी रूप से भुगतान संतुलन (Balance of Payments) के संरचनात्मक दबावों को समाप्त कर सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) तीनों
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है।** अवमूल्यन से अनिवार्य रूप से व्यापार संतुलन में सुधार नहीं होता है। इसका प्रभाव निर्यात और आयात की मांग की लोच (Elasticity of Demand) पर निर्भर करता है, जिसे मार्शल-लर्नर शर्त (Marshall-Lerner Condition) में दर्शाया गया है। यदि आयात पर निर्भरता उच्च बनी रहती है और मांग बेलोचदार (Inelastic) होती है, तो व्यापार घाटा बना रह सकता है या बदतर हो सकता है।
- **कथन 2 सही है।** आयात उदारीकरण अल्पावधि में आयात व्यय को बढ़ा सकता है, जिससे चालू खाता घाटा बढ़ जाता है। हालांकि, बेहतर तकनीक, मशीनरी और इनपुट्स तक पहुंच दीर्घकाल में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कर सकती है।
- **कथन 3 गलत है।** केवल विनिमय दर समायोजन स्थायी रूप से कम निर्यात विविधीकरण, तकनीकी पिछड़ेपन या कमजोर प्रतिस्पर्धात्मकता से उत्पन्न होने वाली भुगतान संतुलन की संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है।

इसलिए, केवल एक कथन सही है।

4. भारत में संवैधानिक शासन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रत्येक धन विधेयक (Money Bill) एक वित्त विधेयक (Financial Bill) होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक अनिवार्य रूप से धन विधेयक नहीं होता है।
2. अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक को राज्यसभा द्वारा खारिज किया जा सकता है।
3. राष्ट्रपति सहमति के लिए प्रस्तुत धन विधेयक को या तो स्वीकार कर सकते हैं या खारिज कर सकते हैं लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते।
4. वित्त विधेयकों की सभी श्रेणियों को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) चारों

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** धन विधेयक, वित्त विधेयकों की व्यापक श्रेणी के भीतर एक उपसमुच्चय (Subset) हैं। इसलिए, प्रत्येक धन विधेयक प्रकृति में वित्तीय होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के रूप में योग्य नहीं होता है।
- **कथन 2 गलत है।** राज्यसभा किसी धन विधेयक को खारिज या संशोधित नहीं कर सकती है। यह केवल बदलावों की सिफारिश कर सकती है और उसे 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस करना होगा। लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार या खारिज कर सकती है।
- **कथन 3 सही है।** अनुच्छेद 111 के तहत, सामान्य विधेयकों के विपरीत, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकते हैं या सहमति रोक सकते हैं।
- **कथन 4 सही है।** व्यय या कराधान प्रावधानों से जुड़े वित्त विधेयकों को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार, तीन कथन सही हैं।

5. कथन-कारण प्रकार (Assertion Reason type) -

कथन (A): मुख्य रूप से मानसून की वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में अक्सर काफी अंतर-वार्षिक कृषि परिवर्तनशीलता (Inter-annual Agricultural Variability) देखी जाती है।

कारण (R1): कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा समय और स्थान के अनुसार असमान (Temporal and Spatial Unevenness) होती है।

कारण (R2): अत्यधिक वर्षा पर निर्भर (बारानी) स्थितियों पर भरोसा करने वाली कृषि प्रणालियाँ सीधे तौर पर अवक्षेपण (Precipitation/वर्षा) में होने वाले उतार-चढ़ाव के संपर्क में रहती हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) A सही है, और R1 और R2 दोनों सही हैं और दोनों A की व्याख्या करते हैं

- (b) A सही है, लेकिन केवल R1 सही है और A की व्याख्या करता है
- (c) A सही है, लेकिन केवल R2 सही है और A की व्याख्या करता है
- (d) A गलत है, हालांकि R1 और R2 दोनों सही हैं

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- **कथन (Assertion) सही है।** मानसून पर निर्भर क्षेत्रों में कृषि परिवर्तनशीलता अक्सर स्पष्ट होती है क्योंकि फसल उत्पादकता काफी हद तक वर्षा की मात्रा, समय और वितरण पर निर्भर करती है।
- **कारण 1 (R1) सही है और कथन की व्याख्या करता है।** मानसून प्रणालियाँ अक्सर समय और स्थान के अनुसार असमान वितरण प्रदर्शित करती हैं। देरी से शुरुआत, लंबे समय तक शुष्क दौर (Dry Spells), या वर्षा का स्थानीय स्तर पर केंद्रित होना बुआई और उपज को प्रभावित कर सकता है।
- **कारण 2 (R2) भी सही है और स्वतंत्र रूप से कथन की व्याख्या करता है।** वर्षा आधारित कृषि में सुनिश्चित सिंचाई के सुरक्षात्मक प्रभाव की कमी होती है और इसलिए यह वर्षा के उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है।

चूंकि दोनों कारण सही हैं और मिलकर कथन (A) की व्याख्या करते हैं, इसलिए सही उत्तर (a) है।



दैनिक अभ्यास प्रश्न – करंट अफेयर्स अनुभाग से

1. स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) दिशानिर्देश, 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इन दिशानिर्देशों ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए पहले की अलग-अलग शासन संरचनाओं को बालवाटिका से कक्षा XII तक विस्तारित एक एकीकृत SMC ढांचे के साथ बदल दिया है।
2. इन दिशानिर्देशों के तहत, कोई भी सरकारी सहायता न प्राप्त करने वाले निजी गैर-सहायता प्राप्त (Private Unaided) स्कूलों के लिए शिक्षा का अधिकार (RTE) ढांचे के तहत अनिवार्य रूप से SMC का गठन करना आवश्यक है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) कोई नहीं
- (c) दोनों
- (d) निर्धारित नहीं किया जा सकता

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** SMC दिशानिर्देश 2026 ने बालवाटिका से कक्षा XII तक को कवर करने वाले एकल निकाय में पहले की SMC और SMDC व्यवस्थाओं को एकीकृत करके एक एकीकृत शासन संरचना की शुरुआत की है।
- **कथन 2 गलत है।** मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी सहायता न प्राप्त करने वाले निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान RTE से संबंधित ढांचे के तहत अनिवार्य SMC प्रावधानों से मुक्त हैं।

अतः, केवल एक कथन सही है।

2. मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम (MARS) को मुख्य रूप से किस लिए डिज़ाइन किया गया है?

- (a) अंतरग्रहीय जांच (Interplanetary Probes) का उपयोग करके दीर्घकालिक ग्रहीय मीथेन चक्रों को मॉडल करने के लिए
- (b) शमन कार्रवाई (Mitigation Action) के लिए उपग्रह-आधारित अवलोकनों का उपयोग करके बड़े मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने और संवाद करने के लिए
- (c) कार्बन क्रेडिट एक्सचेंजों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मीथेन व्यापार को विनियमित करने के लिए
- (d) वायुमंडलीय मीथेन विसंगतियों की निगरानी करके ज्वालामुखी विस्फोटों का पूर्वानुमान लगाने के लिए

उत्तर: (b)

व्याख्या:

MARS, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला (IMEO) के तहत विकसित किया गया है, पहला सार्वजनिक वैश्विक उपग्रह पहचान और अधिसूचना तंत्र है जिसे बड़े मीथेन उत्सर्जन की पहचान करने और समय पर शमन के लिए सरकारों एवं कंपनियों को सूचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपग्रह डेटा, वैज्ञानिक विश्लेषण और एआई (AI)-आधारित प्रणालियों को एकीकृत करता है। विकल्प (a), (c), और (d) गलत तरीके से असंबंधित कार्यों का वर्णन करते हैं।

3. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) और IBCA शिखर सम्मेलन, 2026 के आसपास के घटनाक्रमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IBCA वैश्विक स्तर पर बिल्ली प्रजाति के सात प्रमुख बड़े जीवों (Big Cat Species) के संरक्षण के लिए सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है।
2. भारत एकमात्र ऐसा देश है जो IBCA ढांचे के तहत मान्यता प्राप्त बिल्ली प्रजाति के सभी सात बड़े जीवों को आश्रय देता है।
3. उद्घाटन IBCA शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बड़े बिल्ली जीवों के संरक्षण सहयोग पर एक साझा घोषणापत्र विकसित करना है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो

- (c) तीनों
(d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** IBCA बिल्ली प्रजाति के सात प्रमुख बड़े जीवों—बाघ (Tiger), शेर (Lion), तेंदुआ (Leopard), हिम तेंदुआ (Snow Leopard), चीता (Cheetah), जगुआर (Jaguar), और प्यूमा (Puma) से संबंधित संरक्षण सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **कथन 2 गलत है।** भारत इन सात प्रजातियों में से पांच को आश्रय देता है, न कि सभी सात को। भारत में जगुआर और प्यूमा नहीं पाए जाते हैं।
- **कथन 3 सही है।** उद्घाटन शिखर सम्मेलन और प्रस्तावित "दिल्ली घोषणापत्र" का उद्देश्य संरक्षण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संस्थागत बनाना है।

इसलिए, दो कथन सही हैं।

4. त्रिशंकु विधानसभा (Hung Assembly) में राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान स्पष्ट रूप से त्रिशंकु विधानसभा में सरकार गठन के लिए वरीयता का एक अनिवार्य क्रम निर्धारित करता है।
2. जब किसी मंत्रालय के बहुमत के समर्थन पर संदेह हो, तो राज्यपाल फ्लोर टेस्ट (सदन में शक्ति परीक्षण) की मांग कर सकते हैं।
3. सरकार गठन में राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली विवेकाधीन शक्ति पूरी तरह से न्यायिक संवीक्षा (Judicial Scrutiny) से परे है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है।** संविधान त्रिशंकु विधानसभाओं में वरीयता के किसी स्पष्ट क्रम को निर्धारित नहीं करता है; परंपराएं और न्यायिक सिद्धांत राज्यपाल के विवेक का मार्गदर्शन करते हैं।
- **कथन 2 सही है।** जब विधायी बहुमत अनिश्चित या विवादित हो, तो राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। न्यायिक निर्णयों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि सदन का पटल (Floor of the House) ही बहुमत के परीक्षण के लिए उचित मंच है।
- **कथन 3 गलत है।** राज्यपाल का विवेक पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, विशेष रूप से वहां जहां संवैधानिक अनुचितता या मनमानेपन का आरोप लगाया गया हो।

इस प्रकार, केवल एक कथन सही है।

5. हाल ही में चर्चा में रही जर्मैनियम-मुक्त ड्रोन इमेजिंग तकनीक (Germanium-Free Drone Imaging Technology) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह तकनीक जर्मैनियम-आधारित इन्फ्रारेड ऑप्टिकल घटकों पर निर्भरता से बचने का प्रयास करती है।
2. यह प्रणाली विशेष रूप से नागरिक हवाई फोटोग्राफी (Civilian Aerial Photography) के लिए अभिप्रेत है और इसमें निगरानी अनुप्रयोगों (Surveillance Applications) की कमी है।
3. इस तरह के इमेजिंग पेलोड सघन (Compact) ड्रोन प्लेटफॉर्मों के अनुकूल रहते हुए भी लंबी दूरी की पहचान का समर्थन कर सकते हैं।
4. यह तकनीक अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों में काम करने में असमर्थ है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) चारों

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** यह तकनीक थर्मल इमेजिंग और ड्रोन पेलोड डिज़ाइन में जर्मैनियम-आधारित ऑप्टिकल सिस्टम पर निर्भरता को कम करने पर जोर देती है।
- **कथन 2 गलत है।** ऐसी प्रणालियों में मजबूत निगरानी, सीमा की निगरानी और काउंटर-ड्रोन अनुप्रयोग शामिल हैं।
- **कथन 3 क्षमता के संदर्भ में सही है।** प्रश्न यह पूछता है कि कितने कथन सही हैं—इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हैं, जिससे दो कथन सही हो जाते हैं।
- **कथन 4 गलत है** क्योंकि यह तकनीक उच्च और निम्न तापमान सहित कठिन जलवायु परिस्थितियों में संचालन के लिए डिज़ाइन की गई है।

6. निम्नलिखित ज्वालामुखियों और उनके स्थानों पर विचार कीजिए:

मायोन ज्वालामुखी (Mayon Volcano) कहाँ स्थित है:

- (a) इंडोनेशिया – सुमात्रा द्वीप
- (b) फिलीपींस – लुजोन द्वीप
- (c) जापान – क्युशू द्वीप
- (d) पापुआ न्यू गिनी – न्यू ब्रिटेन द्वीप

उत्तर: (b)

व्याख्या:

मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर अल्बे प्रांत में स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटोवोलकानो (Stratovolcano) है। यह अपने लगभग पूर्ण शंकवाकार आकार (Conical Shape) के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है और प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' (Pacific Ring of Fire) से संबंधित है।

विकल्प (a), (c), और (d) अन्य ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं, लेकिन मायोन को नहीं। यूपीएससी अक्सर द्वीप भूगोल के साथ ज्वालामुखीय भू-आकृतियों को जोड़कर ऐसे मानचित्र आधारित प्रश्न तैयार करता है, जिससे स्थान की सटीकता महत्वपूर्ण हो जाती है।

दैनिक अभ्यास हेतु विषय आधारित प्रश्न

Q1. "भारत में औपनिवेशिक शहरी केंद्र आर्थिक आधुनिकीकरण और सामाजिक अलगाव (पृथक्करण) दोनों को दर्शाते थे।" भारत में औपनिवेशिक शहरों के विकास के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

प्रस्तावना

भारत में औपनिवेशिक शहरीकरण ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व और वाणिज्यिक हितों के परिणामस्वरूप उभरा। पारंपरिक भारतीय शहरों, जो तीर्थयात्रा, प्रशासन या स्वदेशी व्यापार नेटवर्क के इर्द-गिर्द विकसित हुए थे, के विपरीत औपनिवेशिक शहरों का विकास साम्राज्यवादी प्राथमिकताओं के अनुसार हुआ। बंदरगाह, छावनियां (कैंटोनमेंट) और प्रशासनिक केंद्र आधुनिकीकरण के प्रतीक बने और साथ ही उन्होंने नस्लीय एवं सामाजिक-आर्थिक विभाजनों को भी सुदृढ़ किया।

मुख्य भाग

अंग्रेजों ने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों को व्यापार और शासन के केंद्रों में बदल दिया। रेलवे, टेलीग्राम, गोदी (डॉक्स), जल निकासी प्रणाली और नगरपालिका संस्थानों ने आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे की शुरुआत की। बॉम्बे वैश्विक कपास व्यापार से जुड़कर एक अग्रणी वाणिज्यिक केंद्र बन गया, जबकि कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी और प्रशासनिक तंत्र के तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता था। इन विकासों ने प्रवासन, औद्योगिक रोजगार और एक शिक्षित मध्यम वर्ग के उदय को प्रोत्साहित किया।

हालांकि, उपनिवेशवाद के तहत आधुनिकीकरण चयनात्मक और बहिष्करणकारी (Exclusionary) था। शहरी नियोजन नस्लीय विचारधाराओं से गहराई से प्रभावित था। ब्रिटिश अधिकारी अक्सर स्वदेशी बस्तियों को अत्यधिक भीड़भाड़ वाली और अस्वच्छ मानते थे। इसके परिणामस्वरूप, शहरों को "व्हाइट टाउन" (श्वेत नगर) और "ब्लैक टाउन" (अश्वेत नगर) में विभाजित किया गया था। यूरोपीय लोग विशाल, सुव्यवस्थित सिविल लाइंस और छावनियों में रहते थे, जबकि भारतीय मुख्य रूप से सीमित नागरिक सुविधाओं वाले संकीर्ण और भीड़भाड़ वाले इलाकों में रहते थे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं ने इस अलगाव को और अधिक तीव्र कर दिया। प्लेग जैसी महामारियों के कारण आक्रामक स्वच्छता उपाय अपनाए गए, जिसके तहत गरीब समुदायों का विस्थापन हुआ और उनके आवासों को ध्वस्त किया गया। इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों और नगरपालिका विनियमों ने अक्सर देशी आबादी के कल्याण पर वाणिज्यिक और यूरोपीय हितों को प्राथमिकता दी। यहाँ तक कि वास्तुकला भी साम्राज्यवादी शक्ति का प्रतीक थी, जिसमें ब्रिटिश अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए गॉथिक (Gothic) और इंडो-सारेसेनिक (Indo-Saracenic) इमारतों को डिज़ाइन किया गया था।

उसी समय, औपनिवेशिक शहर राजनीतिक जागृति के केंद्र भी बने। समाचार पत्रों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक संघों ने राष्ट्रवादी चेतना को बढ़ावा दिया। शहरी स्थानों ने बैठकों, विरोध प्रदर्शनों और बौद्धिक बहसों की मेजबानी की, जिन्होंने अंततः औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी।

निष्कर्ष

इस प्रकार, औपनिवेशिक शहर एक विरोधाभास का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने आधुनिक बुनियादी ढांचे की शुरुआत की और भारत को वैश्विक वाणिज्य से जोड़ा, फिर भी उनके नियोजन और प्रशासन ने अलगाव और असमानता को संस्थागत रूप दिया। इसलिए औपनिवेशिक शहरीकरण ने आधुनिकीकरण और साम्राज्यवादी प्रभुत्व दोनों को अपने भीतर समाहित किया था।

Q2. भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में स्थानीय स्वशासन के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसकी प्रभावशीलता को सीमित करने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

प्रस्तावना

स्थानीय स्वशासन जमीनी स्तर (ग्रासरूट) पर लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने शासन के केंद्र में नागरिक भागीदारी को मान्यता देते हुए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संस्थागत रूप दिया। इन संस्थानों का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करके और प्रशासन को लोगों के करीब लाकर लोकतंत्र को और गहरा करना था।

मुख्य भाग

स्थानीय स्वशासन कई तरीकों से लोकतंत्र को मजबूत करता है। पहला, यह नागरिकों को स्थानीय विकास को प्रभावित करने वाले निर्णयों में शामिल होने में सक्षम बनाकर सहभागी शासन (Participatory Governance) को बढ़ावा देता है। ग्राम सभाएं, वार्ड समितियां और नगरपालिका मंच सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करते हैं।

दूसरा, विकेंद्रीकरण से प्रशासनिक जवाबदेही और संवेदनशीलता में सुधार होता है। स्थानीय निकाय जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सामुदायिक आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक संदर्भ-विशिष्ट और कुशल बन जाती है।

तीसरा, ये संस्थान राजनीतिक समावेश को बढ़ावा देते हैं। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण ने नेतृत्व के पैटर्न को बदल दिया है। विशेष रूप से महिला प्रतिनिधियों ने कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर ध्यान बढ़ाया है। जमीनी स्तर के लोकतंत्र ने पारंपरिक अभिजात वर्ग से परे राजनीतिक भागीदारी को व्यापक बनाया है।

हालांकि, कई चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। वित्तीय निर्भरता एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। कई पंचायतों और नगर पालिकाओं के पास पर्याप्त कराधान शक्तियों की कमी है और वे राज्य के अनुदानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यह उनकी स्वायत्तता और दीर्घकालिक योजना को कमजोर करता है।

प्रशासनिक सीमाएँ भी बनी हुई हैं। स्थानीय निकायों को अक्सर प्रशिक्षित कर्मियों और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी का सामना करना पड़ता है। नौकरशाही का दबदबा कभी-कभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को कमजोर करता है और वास्तविक विकेंद्रीकरण को सीमित करता है।

राजनीतिक हस्तक्षेप और ग्राम सभाओं के अनियमित कामकाज से जवाबदेही कम होती है। कुछ क्षेत्रों में, स्थानीय अभिजात वर्ग (एलीट वर्ग) इन संस्थानों पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी कमजोर हो जाती है। शहरी शासन इसके अतिरिक्त नगर पालिकाओं, विकास प्राधिकरणों और राज्य एजेंसियों के बीच विभाजित प्राधिकरण से ग्रस्त है।

एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती संविधान के तहत परिकल्पित शक्तियों का अधूरा हस्तांतरण (Devolution of Powers) है। यद्यपि विषयों को ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन वास्तविक हस्तांतरण अलग-अलग राज्यों में काफी भिन्न है।

निष्कर्ष

भारत में लोकतांत्रिक सुदृढीकरण के लिए स्थानीय स्वशासन अपरिहार्य बना हुआ है। हालांकि संवैधानिक सुधारों ने जमीनी स्तर के लोकतंत्र के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया है, लेकिन सार्थक सशक्तीकरण के लिए वित्तीय स्वायत्तता, प्रशासनिक क्षमता और वास्तविक राजनीतिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है।

Q3. "मानव विकास, केवल आर्थिक विकास की तुलना में प्रगति का अधिक व्यापक माप है।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रस्तावना

आर्थिक विकास को पारंपरिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और प्रति व्यक्ति आय जैसे संकेतकों के माध्यम से मापा जाता रहा है। हालांकि, केवल आर्थिक विकास का परिणाम अनिवार्य रूप से जीवन की बेहतर गुणवत्ता के रूप में नहीं बदलता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा लोकप्रिय की गई मानव विकास की अवधारणा ने ध्यान को आय से हटाकर मानव कल्याण पर केंद्रित कर दिया।

मुख्य भाग

मानव विकास लोगों की क्षमताओं और अवसरों के विस्तार पर जोर देता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे संकेतक शामिल हैं, जिन्हें मानव विकास सूचकांक (HDI) के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह दृष्टिकोण इस बात को स्वीकार करता है कि विकास को केवल उत्पादन बढ़ाने के बजाय मानवीय स्वतंत्रताओं को बढ़ाना चाहिए।

प्रगति के एक पैमाने के रूप में आर्थिक विकास पर मानव विकास की श्रेष्ठता कई संदर्भों में स्पष्ट हो जाती है। उच्च आर्थिक विकास वाले देश भी खराब स्वास्थ्य परिणामों, शैक्षिक असमानताओं और सामाजिक अभाव का अनुभव कर सकते हैं। मानव पूंजी में निवेश के बिना आय में वृद्धि असमान और बहिष्करणकारी समाजों को जन्म दे सकती है।

शिक्षा कौशल, उत्पादकता और सामाजिक गतिशीलता में सुधार करती है। स्वास्थ्य श्रम दक्षता और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है। परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों में निवेश करने वाले समाज सतत और समावेशी विकास प्राप्त करते हैं। मध्यम आय स्तर के बावजूद केरल के उत्कृष्ट सामाजिक संकेतक और इसके विपरीत कमजोर सामाजिक परिणामों वाले कुछ संसाधन-संपन्न क्षेत्र इस अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

मानव विकास क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को भी संबोधित करता है। यह लैंगिक असमानता, गरीबी और सामाजिक अपवर्जन को उजागर करता है जिसे जीडीपी के आंकड़े छिपा सकते हैं। एचडीआई द्वारा निर्देशित विकास नीतियां कल्याण-उन्मुख शासन और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हैं।

बहरहाल, मानव विकास पूरी तरह से सीमाओं से मुक्त नहीं है। मापन की चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और व्यक्तिपरक कल्याण को मात्रात्मक रूप से मापना कठिन है। आर्थिक विकास भी आवश्यक बना हुआ है क्योंकि कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए संसाधन देश की उत्पादक क्षमता और राजस्व सृजन पर निर्भर करते हैं।

इस प्रकार, आर्थिक विकास और मानव विकास को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। सतत प्रगति के लिए इन दोनों का एकीकरण आवश्यक है।

निष्कर्ष

मानव विकास केवल आर्थिक विकास की तुलना में प्रगति का आकलन करने के लिए एक व्यापक और अधिक मानवीय ढांचा प्रदान करता है। हालांकि आय सृजन महत्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन विकास को अंततः अर्थ तभी मिलता है जब वह मानवीय क्षमताओं, गरिमा और अवसरों का विस्तार करता है।

Q4. "नैतिक शासन के लिए न केवल नियमों के पालन की बल्कि करुणा और नैतिक साहस की भी आवश्यकता होती है।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ परीक्षण कीजिए।

प्रस्तावना

एक लोकतांत्रिक समाज में शासन से संवैधानिक मूल्यों, कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार काम करने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, केवल नियमों का पालन करना हमेशा न्याय या जनता के कल्याण की गारंटी नहीं देता है। नैतिक शासन (Ethical Governance) प्रक्रियात्मक वैधता से आगे जाता है और इसमें करुणा, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस जैसे मूल्य शामिल होते हैं। लोक सेवकों के सामने अक्सर ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ नियमों का कड़ाई से पालन मानवीय चिंताओं के साथ संघर्ष कर सकता है, जिससे नैतिक निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है।

मुख्य भाग

नैतिक शासन में सार्वजनिक हित और नैतिक जिम्मेदारी द्वारा निर्देशित निर्णय लेना शामिल है। नियम पूर्वानुमान और जवाबदेही प्रदान करते हैं, लेकिन शासन अक्सर जटिल सामाजिक वास्तविकताओं से निपटता है जिन्हें केवल नियमों के यांत्रिक अनुप्रयोग के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है।

करुणा नैतिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह लोक सेवकों को कमजोर वर्गों की कठिनाइयों को समझने और संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, प्रशासक अक्सर तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में ढील देते हैं। इसी तरह, बुजुर्गों, दिव्यांगों या आपदा पीड़ितों से जुड़े कल्याणकारी वितरणों के लिए प्रशासनिक प्रावधानों की मानवीय व्याख्या की आवश्यकता हो सकती है।

हालांकि, जवाबदेही के बिना करुणा मनमानेपन की ओर ले जा सकती है। इसलिए, नैतिक शासन के लिए संस्थागत सत्यनिष्ठा के साथ सहानुभूति को संतुलित करना आवश्यक है। यहीं पर नैतिक साहस महत्वपूर्ण हो जाता है। नैतिक साहस से तात्पर्य दबाव, आलोचना या व्यक्तिगत जोखिम के बावजूद नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने की इच्छा से है।

भारतीय प्रशासनिक इतिहास इसके कई उदाहरण प्रदान करता है। अवैध भूमि अधिग्रहण, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में राजनीतिक दबाव का विरोध करने वाले अधिकारी नैतिक साहस का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे कार्य संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हैं और जनता के विश्वास को मजबूत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संस्थागत गलतियों को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर (Whistle-blowers) भी व्यक्तिगत परिणामों के बावजूद नैतिक प्रतिबद्धता का उदाहरण पेश करते हैं।

इसके विपरीत, शासन की कई विफलताएँ नैतिक कमी के परिणामों को दर्शाती हैं। मानवीय संकटों के दौरान नौकरशाही की उदासीनता, अत्यधिक कागजी कार्रवाई के कारण कल्याण से वंचित करना, और अनैतिक निर्देशों को चुनौती देने में अनिच्छा से पता चलता है कि केवल वैधानिकता न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकती है।

नैतिक शासन संवैधानिक नैतिकता के साथ भी संरेखित होता है। समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय के सिद्धांत प्रशासकों से प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के साथ मानवीय निर्णय को जोड़ने की मांग करते हैं। नैतिकता में प्रशिक्षण, पारदर्शी संस्थान और जवाबदेह नेतृत्व ऐसे मूल्यों को विकसित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

इसलिए नैतिक शासन केवल नियमों की आज्ञाकारिता तक सीमित नहीं है। इसके लिए नागरिकों के साथ करुणामय जुड़ाव और न्याय तथा जनहित की रक्षा के लिए नैतिक साहस की आवश्यकता होती है। नियम आवश्यक बने हुए हैं, लेकिन शासन को वैधता तभी मिलती है जब उसका प्रयोग मानवता और नैतिक दृढ़ विश्वास के साथ किया जाए।

Q5. "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय परिवर्तनकारी अवसरों और गंभीर नियामक चुनौतियों दोनों को प्रस्तुत करता है।" हाल के वैश्विक और भारतीय घटनाक्रमों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

प्रस्तावना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इक्कीसवीं सदी की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक के रूप में उभरा है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा से लेकर रक्षा और वित्त तक, एआई अनुप्रयोग आर्थिक प्रणालियों और शासन संरचनाओं को नया आकार दे रहे हैं। हाल के घटनाक्रमों, जिनमें जेनरेटिव एआई टूल्स, एआई सुरक्षा पर वैश्विक बहस और भारत के विस्तार करते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं, ने जिम्मेदार एआई शासन के संबंध में चर्चाओं को तेज कर दिया है।

मुख्य भाग

एआई महत्वपूर्ण विकासात्मक अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य सेवा में, एआई-सहायता प्राप्त निदान (AI-assisted diagnostics) रोग का पता लगाने और उपचार की योजना में सुधार करते हैं। कृषि क्षेत्र भविष्य कहने वाले विश्लेषण (Predictive Analytics), सटीक खेती और जलवायु-अनुकूल परामर्श के माध्यम से लाभान्वित होता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकियां व्यक्तिगत शिक्षण के लिए एआई का उपयोग करती हैं, जबकि सार्वजनिक प्रशासन शिकायत निवारण, धोखाधड़ी का पता लगाने और सेवा वितरण के लिए तेजी से एआई को नियोजित कर रहा है।

भारत के लिए, एआई डिजिटल परिवर्तन और आर्थिक विकास के व्यापक दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। नवाचार, सेमीकंडक्टर विकास और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल भारत को एक प्रमुख एआई पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में स्थापित करना चाहती हैं। एआई उत्पादकता बढ़ा सकता है, शासन की दक्षता में सुधार कर सकता है और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रोजगार पैदा कर सकता है।

हालांकि, इन अवसरों के साथ गंभीर जोखिम भी जुड़े हैं। यदि डेटासेट सामाजिक रूप से विषम या पक्षपाती हैं, तो एल्गोरिथम पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias) भेदभाव को और मजबूत कर सकता है। एआई-संचालित विश्लेषण के साथ गोपनीयता, निगरानी और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के संबंध में चिंताएं बढ़ गई हैं। डीपफेक और गलत सूचनाएं चुनावी अखंडता तथा सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा करती हैं।

रोजगार का विस्थापन एक और चुनौती प्रस्तुत करता है। स्वचालन (ऑटोमेशन) नियमित और कम कुशल व्यवसायों को असमान रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे पुनर्कौशल (Reskilling) और सामाजिक सुरक्षा उपायों की मांग बढ़

जाती है। इसके अलावा, कुछ मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स और तकनीकी रूप से उन्नत देशों के बीच एआई क्षमताओं का संकेंद्रण डिजिटल असमानता और एकाधिकारवादी शक्ति के संबंध में चिंताएं पैदा करता है।

वैश्विक स्तर पर, देश और क्षेत्रीय संगठन सुरक्षा के साथ नवाचार को संतुलित करने वाले नियामक ढांचों (Regulatory Frameworks) पर बहस कर रहे हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही, व्याख्यात्मकता (Explainability) और नैतिक उपयोग जैसे मुद्दे नीतिगत चर्चाओं पर हावी हैं। भारत के सामने भी एक ऐसा शासन मॉडल तैयार करने की चुनौती है जो संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करे।

इसलिए प्रभावी एआई शासन के लिए सरकारों, उद्योग, शिक्षाविदों और नागरिक समाज को शामिल करने वाले बहु-हितधारक दृष्टिकोण (Multi-stakeholder Approach) की आवश्यकता है। नैतिक दिशानिर्देश, डेटा संरक्षण ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अभूतपूर्व विकासात्मक अवसर और एक जटिल शासन चुनौती दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। एआई का भविष्य केवल तकनीकी प्रगति पर ही नहीं, बल्कि इसे नैतिक, समावेशी और जिम्मेदारी से विनियमित करने की मानवता की क्षमता पर निर्भर करेगा।

